



लोक उद्यम विभाग

प्रलिस के लल

लोक उद्यम विभाग, महारतन, नवरतन, मनीरतन, प्राककलन समतल, सार्वजनक क्षेत्र के उद्यम,

मेन्स के लल

सार्वजनक उद्यम विभाग के कार्य तथा इसे वतलत मंत्रालय के दायरे में लाने के नरुणय का महत्त्व

चरचा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सार्वजनक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises-DPE) को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर पुनः वतलत मंत्रालय के दायरे में ला दलल है ।

- वतलत मंत्रालय में अब छह विभाग होंगे जबकल DPE के मूल मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनक उद्यम मंत्रालय को अब केवल भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाएगा ।

परमुख बढु

सार्वजनक उद्यम विभाग के वषलत में:

- लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनक क्षेत्र के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) का नोडल विभाग है और CPSEs से संबधतल नीतलथी तैयार करता है ।
 - CPSEs ऐसी कंपनलथी हैं जनलमें केंद्र सरकार या अन्य CPSEs की परतुयकष हसलसेदारी 51% या उससे अधकल है ।
- यह वषलष रूप से, CPSEs में नषलपादकता सुधार एवं मूलयांकन, स्वायतुतता तथा वतलतीय शक्तलथी के परतुयायोजन और कारुमकल परबंधन के बारे में नीतगत दशलानरलदेश तैयार करता है ।
- इसके अलावा यह केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबधतल बहुत से क्षेत्रों के संबध में सूचना एकतुर करता है और उसका रखरखाव भी करता है ।
 - यह अब आरुथकल मामले, राजसुव, वयय, वतलतीय सेवाएँ और नवलश तथा सार्वजनक संपतुतल परबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management-DIPAM) के अलावा वतलत मंत्रालय में छटा विभाग होगा ।
- DPE को वतलत मंत्रालय में स्थानांतरलत कलत जाने से CPSEs के पूंजीगत वयय, परसलपतुतल मुदरीकरण और वतलतीय स्वासुथ्य की कुशल नगरलनी में मदद मललगी ।

पृष्ठभूमल:

- तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राककलन समतल (Estimates Committee) ने अपनी रपुॉरट में, एक केंद्रीकृत समनुवय इकाई स्थापतल करने की आवश्यकता पर बल दलल था, जो सार्वजनक उद्यमों के परदर्शन का नरुंतर मूलयांकन भी कर सके ।
- जसलके परणलामसुवरूप वरष 1965 में वतलत मंत्रालय के अंतरगत सार्वजनक उद्यम बयूरो (Bureau of Public Enterprises-BPE) की स्थापना हुई ।
- वरष 1985 में, BPE को उद्योग मंत्रालय का हसलसा बनाया गया था । मई 1990 में BPE को एक पूरण विभाग बनाया गया जसल लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises- DPE) के रूप में जाना जाता है ।

परमुख कार्य:

- सभी लोक उद्यमों (Public Sector Enterprises- PSEs) को परभावतल करने वाले सामान्य नीतलसंबंधी मामलों का समनुवय ।
- लोक उद्यमों का पुनरुगठन करने या बंद करने तथा उनके ललत तंतर से संबधतल सलाह देना ।
- पुनरुदधार से संबधतल सलाह देना ।

- सर्वैच्छक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में **कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं उनका पुनर्वास** ।
- **'रतन' का दर्जा** देने सहित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का अन्य प्रकार का **वर्गीकरण** ।
 - CPSEs को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- **महारतन, नवरतन और मनीरतन** । वर्तमान में 10 महारतन, 14 नवरतन और 74 मनीरतन CPSEs हैं ।

CPSEs का वर्गीकरण

श्रेणी

- महारतन
- नवरतन
- मनीरतन

शुरुआत

- CPSEs के लिये **महारतन योजना** मई, 2010 में शुरू की गई थी, ताकि **मिगा CPSEs को अपने संचालन का वसितार करने और वैश्विक दृष्टि** के रूप में उभरने के लिये **सशक्त बनाया जा सके** ।
- **नवरतन योजना वर्ष 1997** में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और **वैश्विक खिलाड़ी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन** करते हैं ।
- **मनीरतन योजना की शुरुआत वर्ष 1997** में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी ।

मानदंड

महारतन:

- कंपनियों को **नवरतन का दर्जा** प्राप्त होना चाहिये ।
- कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और वनियम बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिये ।
- वित्त तीन वर्षों की अवधि में **औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहिये ।
- पिछले तीन वर्षों में **औसत वार्षिक नवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहिये ।
- पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) **5,000 करोड़ रुपये से अधिक** होना चाहिये ।
- कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये ।
- **उदाहरण:** भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि ।

नवरतन:

- **मनीरतन श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs**, जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो । ये छह मापदंड हैं:
 - शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ
 - उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत
 - मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्कगि कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज
 - ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर
 - प्रतिशेयर कमाई
 - अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन
- **उदाहरण:** भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदि ।

मनीरतन:

- **मनीरतन श्रेणी- 1:** मनीरतन कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने **पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया** हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो ।
 - **उदाहरण (श्रेणी- I):** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंटरकिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदि ।
- **मनीरतन श्रेणी- 2 :** CPSE द्वारा **पिछले तीन साल से लगातार लाभ अर्जित किया हो** और उसकी नवल संपत्तिसकारात्मक हो, वे मनीरतन-II का दर्जा देने के लिये पात्र हैं ।
 - **उदाहरण (श्रेणी- II):** भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL), आदि ।
- मनीरतन CPSE को सरकार के किसी भी ऋण पर ऋण / ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिये ।
- मनीरतन CPSE कंपनियाँ **बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे** ।

प्राक्कलन समिति

परिचय :

- इसे प्रथम बार 1920 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति वर्ष 1950 में स्थापित की गई थी।
- यह समिति बिजट में शामिल अनुमानों की जाँच करती है तथा सार्वजनिक व्यय में 'अर्थनीति' का सुझाव देती है।
- संसद की अन्य वित्तीय समितियों में शामिल है - लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति।

सदस्य:

- इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा ये सभी सदस्य लोकसभा से होने चाहिये।
- सदस्यों को लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुना जाता है, ताकि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
- किसी मंत्री को प्राक्कलन समिति के सदस्य/अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्यों में से की जाती है।

कार्य:

- यह समिति व्यय में मतिव्ययिता और दक्षता की रिपोर्ट करने का प्रयास करती है।
- यह सुझाव देती है कि नीतियाँ प्रशासनिक ढाँचे में क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा मतिव्ययिता एवं दक्षता लाने के लिये कनिष्ठ वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया जा सकता है।
 - इस समिति का कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर चलता रहता है तथा यह परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सदन को रिपोर्ट करती रहती है।
 - इसी कारण इस समिति को 'सतत अर्थव्यवस्था समिति' भी कहा जाता है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस